

Oil Steady Ahead of US Fed's Rate Decision

Reuters

Oil prices traded in a narrow range on Wednesday as investors stayed cautious ahead of a potential interest rate cut by the US Federal Reserve and its projections for 2025, while a draw in US crude inventories offered some support. Brent futures rose 42 cents, or 0.57%, to \$73.61 a barrel at 1201 GMT, while US West Texas Intermediate crude climbed 47 cents, or 0.67%, to \$70.55 a barrel.

The Fed is expected to cut rates by a quarter point, but to signal a cautious approach to loosening monetary policy next year.

"A quarter-point cut itself is unlikely to shake markets much. Investors may

focus more on hints and clues on how likely a January pause is, as well as on how many rate cuts policymakers are contemplating throughout 2025," said Charalampos Pissouros, senior investment analyst at brokerage XM. The US central bank will release its policy statement at 1900 GMT, followed by remarks from Chair Jerome Powell.

Lower rates decrease borrowing costs, which can boost economic growth and demand for oil.

"Oil prices ought to see more of a reaction to the crude inventory draw seen in the API data overnight... however, such is the diverting power of central bank rate decisions that investors in all of the trading mediums are taking a very light touch to proceedings"



said John Evans, analyst with oil broker PVM. In the U.S., American Petroleum Institute data on Tuesday showed that crude stocks fell by 4.69 million barrels in the week ended Dec. 13, a source said. Gasoline inventories rose by 2.45 million barrels, and distillate stocks rose by 744,000 barrels, according to the source. Analysts projected U.S. energy firms pulled about 1.6

million barrels of crude from storage during the week ended December 13, according to a Reuters poll.

The US Energy Information Administration will release its oil storage data on Wednesday.

"Trade war fears and uncertainty on how aggressively the U.S. Fed will cut interest rates next year is likely capping the upside for now," UBS analyst Giovanni Staunovo said.

"There is a prevailing narrative that Trump's policies may lead to inflation, which, coupled with concerns about potential interference with the Federal Reserve's autonomy, is causing oil investors to remain cautious," said Priyanka Sachdeva, senior market analyst with Phillip Nova.

केंद्र ने बिहार में 47 इथेनॉल परियोजनाओं को ऋण सब्सिडी के लिए मंजूरी दी



एजेंसी ■ नई दिल्ली

सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि बिहार की कुल 47 परियोजनाओं को नई डिस्टिलरी स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के वास्ते सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई है। खाद्य राज्य मंत्री निमुबेन जयतिभाई बंभानिया ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा

कि वर्तमान में बिहार में 22 इथेनॉल डिस्टिलरी चालू हैं, जिनमें आठ गुड़ आधारित और 14 अनाज आधारित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसमें तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेच रही हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने और मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्र ने 2018 से 2022 तक विभिन्न इथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाएं शुरू की हैं।

मुख्य सचिव ने घरों तक गैस पहुंचाने की योजना के क्रियान्वयन पर असंतोष जताया

राजमार्ग, रेलवे, पावर, टेली कम्युनिकेशन और गैस परियोजनाओं की समीक्षा

भास्कर न्यूज़ | पटना

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बिहार में चलाई जा रही इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा में घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने वाली योजना के क्रियान्वयन पर असंतोष जताया। बुधवार को उन्होंने दक्षिणी बिहार में चलाई जा रही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग परियोजनाओं, रेलवे, पावर, टेली कम्युनिकेशन और गैस परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सिटी गैस सप्लाई में अबतक लगभग 7 लाख घरों तक गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य था, लेकिन उसमें संतोषजनक उपलब्धि नहीं हो पाई है। उसके बाद मुख्य सचिव ने राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव को संबंधित गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों के साथ

पटना-आरा-सासाराम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का टेंडर फाइनल

बैठक में यह बात सामने आई कि पटना-आरा-सासाराम ग्रीन फील्ड फोरलेन हाईवे परियोजना के भू-अर्जन के लिए मुआवजे का वितरण शुरू किया जा रहा है। तीनों जिलों रोहतास, भोजपुर और पटना में एक महीने के अंदर एनएचएआई को पथ का सीमांकन सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है। परियोजना का टेंडर हो गया है। फरवरी-मार्च तक कार्य आवंटन हो जाएगा। वहीं वाराणसी-कोलकता एक्सप्रेस-वे में कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में कार्य प्रारंभ हो चुका है। मुंगेर-भागलपुर-मिर्जाचौकी और आमस-दरभंगा फोरलेन परियोजनाओं का काम चल रहा है। रेलवे परियोजनाओं में सोन नगर-अंडाल डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, सासाराम रेल ओवर रेल, आरा वाई कर्व, सोन नगर लूप लाइन आदि परियोजनाओं का कार्यान्वयन ठीक गति से चल रहा है। बैठक में केंद्र की एजेंसियों द्वारा यह बताया गया कि राज्य में भूमि की उपलब्धता के कारण परियोजना में काम प्रभावित नहीं है। सभी परियोजनाओं में आवश्यक भूमि उपलब्ध हो रही है।

मासिक समीक्षा करने का निर्देश दिया। इससे राज्य में उपभोक्ताओं को पाइप गैस सप्लाई शीघ्र मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी परियोजनाओं के लिए हर जिले में परियोजनावार उप समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी

नामित किया गया है, जो हर 15 दिन पर परियोजना स्थल का भ्रमण करके ऑनलाइन रिपोर्ट समर्पित करेंगे। इस मौके पर दूरसंचार मंत्रालय से राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बचे कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया गया।